माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, श्री नीतीश कुमार के द्वारा दिनांक– 19.05.2015 को दिये गये भाषण का ट्रांसक्रिप्सन

वन एवं पर्यावरण, योजना एवं विकास तथा शिक्षा मंत्री श्री पी०के० शाही जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह जी, फॉरेस्ट रिचर्स इंस्टीट्यूट देहरादून के निदेशक श्री वी०पी० घोष, वैद्य जी, वन एवं पर्यावरण के प्रधान सचिव विवेक सिंह, श्रीमती असुंली आर्या जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री जनाब वशी अहमद खान साहब, यहाँ उपस्थित पर्यावरण एवं वन विभाग के सभी पदाधिकारीगण तथा गंगा के लिए वानिकी गतिविधियों पर परामर्श बैठक में भाग ले रहे राज्य के और राज्य के बाहर के सभी प्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सज्जनों।

आज आप के बीच उपस्थित होकर एवं भाग लेकर प्रसन्नता हो रही है। अरण्य भवन का आज उद्घाटन हुआ है। इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने और प्रधान सचिव जी ने भी चर्चा की है। ग्रीन बिल्डिंग के तर्ज पर इसका निमार्ण हुआ है और मुझे इससे खुशी हो रही है कि इस अवसर पर भवन के निर्माण की योजना को मंजूरी देने का अवसर मिला। शिलान्यास करने का अवसर मिला और आज उसका उद्घाटन करने का भी अवसर मिला। इस लिए आज मुझे खुशी हो रही है। और मैं समझता हूँ कि वन विभाग के कार्य में पूरी सहूलियत होगी। इसके जितने निदेशालय हैं और इसकी गतिविधियां हैं, यहाँ से संचालित हो सकेगी और मेरी समझ से जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, ''हरियाली मिशन'' जो मिशन मोड में चलाया जा रहा है और जो हमारे कृषिरोड मैप का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसकी सभी गतिविधियों का अनुसरण यहाँ से किया जा सकेगा। झारखंड

के निर्माण के बाद जो शेष बचा हुआ बिहार था, उसमें फॉरेस्ट के बारे में कोई सोच नहीं था चाहे वे नीतियाँ बनाने वाले, कार्यक्रमों को लागू करने वाले हो, सबों के बीच में ये एक धारणा बनी हुई थी कि झारखंड के अलग होने के बाद जंगल तो सब चला गया। अब यहाँ कोई जंगल तो हैं ही नहीं इसलिए वन का तो कोई औचित्य नहीं है। वन विभाग की छाप पड़ती रहती थी लेकिन फॉरेस्ट का तो उसी समय उसकी छाप दिखाई पड़ती थी कि ये एक डिपार्टमेंट है और मैं समझता हूँ कि हमारे इस विभाग के जितने अधिकारी थे वो इसी बात से आनंदित हुए थे कि मेरे पास कुछ अधिकार है। यूँ तो पूरे देश में फॉरेस्ट सर्विस है जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस हैं, एलाएड सर्विस है उसी तरह से फॉरेस्ट सर्विस है। लेकिन फॉरेस्ट सर्विस में तो लोग हैं और जो बिहार में जिनका पदस्थापन हो गया, अब उनके मन में ये बात तो लगती रहती थी कि यहाँ कहाँ फॉरेस्ट है, चलो जो भी हैं कोई अगर ब्रीज बनने वाला हैं, तो कोई सड़क किनारे जितने पेड़ लगे थे उसी को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया। कही फॉरेस्ट है ही नहीं तो फॉरेस्ट एरिया दिखे तो उसको reserve फॉरेस्ट कर दिया गया। reserve फॉरेस्ट तो था नहीं, वो तो वानिकी का कार्यक्रम चलता रहता था अब सड़क का चौड़ीकरण हो। अब widening के लिए अब पेड़ तो कोई काट नहीं सकता तो ये engineering department और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बड़ा conflict हुआ। शुरूआती दिनों में देखने को मिलता था क्योंकि फॉरेस्ट में भी कोई कार्य नहीं हो रहा था रोड के network का expansion हो रहा था तो वैसी स्थिति में उसी समय मुझको लगा कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को कुछ लग रहा है कि हम भी कुछ है। किसी भी काम को हम रोक सकते हैं, ये अधिकार तो उनके पास है तो मैने देखा कि भाई इतना बड़ा महकमा हमारे पास है और इतने

अधिकारी हैं और फॉरेस्ट तो हमारे कम हैं और जो फॉरेस्ट कवर में जिन इलाकों का शुमार भी होता है, वहां के फॉरेस्ट एक तरह से समाप्त हो चुके हैं या बहुत खराब स्थिति में है। कुछ ही इलाको में फॉरेस्ट दिखता था वो चम्पारण में या फिर ये जमुई, बांका के इलाके में, कुछ गया बगैरह के इलाके में और राजगृह में तो ऑलमोस्ट कहीं कोई फॉरेस्ट दिखता ही नहीं था तो हम लोगों ने सोचा कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इतना बड़ा नेटवर्क हमारे पास है और फॉरेस्ट कोर्ट हमारा इतना कम हैं वो इनको इनका जो रेगुलेटरी कार्य है वो तो करते रहेंगे।

चूंकि वो कानून से निकला हुआ है। लेकिन इनके पास कुछ और भी काम होना चाहिए। डेवलपमेंट काम इनके हाथ में होना चाहिए। तो ये फिर बिहार मे ये तय किया गया कि हमें फॉरेस्ट कोर्ट बढ़ाना है। ग्रीन कोर्ट बढ़ाना है और उसके लिये हमलोगों ने हरियाली मिशन का गठन किया। हमने देखा शुरू में कि काम नहीं हो रहा है। शुरू में ही बच्चों को इस काम में लगाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरूआत हम लोगों ने किया। बच्चे जो तीन साल तक देखभाल करेंगे उनको इनसेंटिव मिलेगा। तो यह सब पेड़ कई बार लगाये गये जो वृक्ष लागाये गये हैं पिछले दशकों में, कई वर्षों में जो वृक्ष लगाये गये हैं कि अगर पूरे की गिनती की जाए तब तो बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा अब तक पेड़ों से आच्छादित हो जाना चाहिये था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि पेड़ लगाये जाते हैं और हमने इस बात को बहुत देखा, विधायक रहते हुए हमने खासकर महसूस किया था कि जो पेड़ लगाये गये थे और इस पेड़ की रक्षा में जो बबूल चारों तरफ था तो पेड़ तो पता नहीं की कहां चला गया मगर बबूल रह गया। तो हमारे यहां तो कोई रहता नहीं है लेकिन हम देखते थे कि कई जगह से

ऊंट आता था, तो हमारी जिज्ञासा थी कि भाई यहां ऊंट इधर क्यों आता हैं, तो पता चला कि इधर जो बबूल का पेड़ है, तो बबूल का पेड़ हैं सड़क के दोनों किनारे और जो फिर वाहन गुजरते हैं उनको कठिनाई होती हैं, तो ऊंट आ जाने से उस पेड़ के पत्ते–उत्ता खाता है, बड़ा अच्छा लगता हैं। तो उसने देखा कि भाई मूल पेड़ गायब हो गया है और वो वही लग गया वो कायम रहा और इस प्रकार से लगा कि कितने नहरों पर, नदियों के किनारे, आज तो गंगा नदी के किनारे चर्चा करेंगे यहाँ बैठ कर कि कैसे हो। मुख्य सचिव ने ठीक ही प्रश्न राइज किये हैं। लेकिन उसकी रक्षा नहीं हो पाई तो हम लोगो ने शुरूआत की भी उसी धात वृक्ष रोपण योजना से कि अगर उसकी रक्षा करें तो एक जागृति भी आएगी पेड़ों के प्रति, ये कार्यक्रम शुरू किया था अब तो खैर उसका expansion हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने देखा और इसको हमने कृषि road map में शामिल किया। कृषि road map हमारा आयाम बहुत बड़ा एवं व्यापक हैं, जिसमे forestry है, जिसमें animal husbandry भी हैं, fishry भी हैं, dairy भी हैं, जो भी है हर विकास चाहे वो अन्न का उत्पादन हो, फल का उत्पादन हो, फूलों का उत्पादन हो। हर चीज को उसके अधीन रखा गया है। Agro-forestry तो उसी में इस बात का उल्लेख किया। हमलोगों ने कहा कि सालभर में एक टारगेट बनना चाहिए कि आखिर कुल मिलाकर जिसको फॉरेस्ट कहते हैं। Declaired forest तो 7% के आस पास या उससे थोड़ा ज्यादा लेकिन हमने जब से काम शुरू किया तो 2011 जो उस समय आकड़े उपलब्ध थे उसके हिसाब से बिहार में वृक्षों का आच्छादन हो। tree cover था हमलोग कम से कम tree cover 15% करेंगे और इसको इस योजना को लागू करने के लिए हम लागों ने हरियाली मिशन योजना का गठन किया और उसी के मुताबिक काम किया। और जो forest department का इतना बड़ा Infrastructure है,

इतना Human resources हैं उसको भी लगाया जाये। निजी लोगों को भी प्रोत्साहित किया जाए, तो हमने देखा कि गाड़ी बढ़ नहीं रही थी शुरू के दिनों में, वो हमने अपने political party में ये तय किया कि हमारी पार्टी का member वही बनेगा जो कम से कम एक पेड़ लगायेगा। तो शुरू में लोगों को अटपटा लग रहा था लेकिन धीरे–धीरे लोगों को इसकी पहल समझ में आयी और यकीन मानिये कि ये political आदमी को इन सब चीजो का कहा ख्याल रहता हैं उसमें भी बिहार में। जो छुट्टी ज्यादा हैं। तो भी आप जाइएगा, स्कूल, कॉलेज। तो सब जगह राजनीति पर चर्चा करते हुए मिल जायेगे, यहा एक–एक आदमी राजनीति पर बात करता हैं। बताइये संचालन होता था ज्ञान का केन्द्र था, जो कुछ भी था जिसके चलते हम ढिकते हैं। अन्य प्रदेशो में भी आप जायेगे तो ऐसा माहौल कम दिखेगा, लेकिन बिहार में इस तरह का माहौल कुछ ज्यादा ही है। पॉलिटिकल माहौल होता हैं तो उस पर चर्चा ज्यादा होती हैं, बात–चीत ज्यादा होती है, तो वैसी परिस्थिति में पेड़ लगवाना, वो भी पॉलिटिकल वर्कर से, अपने आप में कठिन कार्य था लेकिन हमने पहला पेड़ लगाया और शुरू किया। मुझे खुशी हुई कि 10 लाख से ज्यादा पेड़ लग गया और सबसे बड़ी बात लगाना शुरू किया, लोगों ने नियंत्रण देना शुरू किया। कहा कि चलिये एक माहौल बना। तो एक दिन हम देख रहे थे कि, वन विभाग और सब लोगों के यहा थोड़ी तेजी नहीं आ रही हैं। हमने कहा कि कोई पढ़ाई फॉरेस्ट का नहीं पढ़ा हैं, पेड़ का नहीं पढ़ा हैं उसको पूरा समझ में आ गया और कहा से इसका पौधा मिलेगा। कोई बनारस से ला रहा है, कोई कलक ाा से ला रहे हैं, बिहार में तो पौधे भी कम मिलते थे। लेकिन वो कार्य म हमारा इतना लोक प्रिय हुआ कि यहा जितनी नर्सरी थी उसमें पौधे नहीं थे, जितने बड़े पैमाने पर पौधों का वितरण किया जा रहा था, पेड़ लगाने के लिये, उनको प्रेरित

करने के लिये तो हो गया। लोगो को समझ में आ गया। तो फिर यहा हमने एक दिन लोगों को कहा कि साहब आप इतना बड़ा establistment है, पूरी सरकार है, पूरा महकमा हैं और आप इस योजना को अभी शुरू नहीं कर पा रहे है और आप देखिये political party ने launch किया और हमारा कोई खुद जिसको कहते हैं, मजबूत संगठन इस प्रकार से नहीं है, हम लोगों का mass part है और वहा इस बात का प्रभाव हो गया और वो पेड़ लगाने लगे और यहा ये शुरू नहीं हुआ तो लगता है कि वो फिर लोगो को भी सिनियर ऑफिसर थे उनको कुछ लगा और तब वे जगे और सब लगे तो *हरियाली मिशन* का काम शुरू हुआ और आज काम इतना बढ़िया चल रहा है कि पिछले साल जो रिपोर्ट आयी हैं tree cover की उसके हिसाब से तो 12.86% हो गयी। यानि कि हम टारगेट के मुताबिक ही नहीं चल रहे हैं, टारगेट से बेहतर हमारा प्रदर्शन है। और उस समय तक हमने पूछा कि 24 करोड़ पेड हमे लगाने हैं और आधे पेड़ भी नहीं लग पाये और तब इतना tree cover हो गया और ये तो कई आधार पर इसका मूल्यांकन हुआ है। सेटेलाइट इमेज लिये जाते हैं और कई प्रकार से उसका मूल्यांकन होता है। तो इससे ये पता चला कि एक तो सरकारी इनिशिएटिव और इसके साथ–साथ लोगों ने भी पेड़ लगाने शुरू किये। तो मुझे खुशी है कि हर जगह पेड़ लगाने शुरू हुए। शहरों में भी अब लोग प्रेरित हुये हैं कि लगाना चाहिये। तो कुल मिलाकर 12.8% तो मुझे तो पूरा भरोसा हैं कि 2017 के पहले ही हम 15% के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और बिहार उसके आगे 17% तक जा सकता हैं। बहुत आगे हम नहीं जा सकते हैं, चूकि हमारे यहा जमीन सीमित है। जमीन का तो हैं expansion हैं नहीं। जमीन का तो expansion नहीं हो सकता हैं। लेकिन आबादी बढती चली जा रही

है। 94000 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है और 11 कड़ोड़ से ज्यादा आबादी है, तो वैसी परिस्थिति में लोगों को इसी में रहना है। सारी गतिविधियाँ इसी में होनी है। आवास ही नहीं सड़क, पूल, रेलवे, दफ्तर, स्कूल, अस्पताल सब कुछ बनते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास जमीन की उपलब्धता कम है। इसलिये अधिकत्म वहाँ तक तो हम जरूर जा सकते है। और इसके अलावे अन्य प्रकार से हम लोग ग्रीन कर सकते हैं तो मुझे खुशी है और इसके लिये मैं सबसे पहले ये जो हरियाली मिशन का काम है वो ठीक ढंग से काम चल रहा है। इसके लिए वन एवं पर्यावरण विभाग को बधाई देता हूँ। मंत्री जी को भी और यहाँ पर तमाम पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ और ये प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए और अधिकतम जो हमारा लक्ष्य है, उससे भी आगे बढ़ना चाहिये, इसका प्रयास होना चाहिए। तो आज अब ये अच्छी बात हैं लोगों में जागृति आ रही है और अगर हम पेड़ नहीं लगायेगे और आज जो मौसम का मिजाज बदल रहा है। हमारे यहाँ बिहार में तो भूकंप की तीव्रता। हर साल flood आने के वावजूद हमारे पृथ्वी की इतनी उर्वरा शक्ति थी लोगो में मेहनत करने की इतनी क्षमता थी ग्रोथ हमारा आगे बढ़ रहा था लेकिन जो मौसम का मिजाज बदल रहा है, इसके बाद वर्षा नहीं होती, लम्बा ड्राई स्पेल होता है, इसके बाद वर्षा हो जाती हैं, तो देर से वर्षा होती है। ये सिलसिला हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। तो ये सब जो असंतुलन पैदा हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा हैं कि इन सबमें climate चेंज का प्रतीक है। और वैसी परिस्थिति में हमे और गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि इस बदलते क्लाईमेट में क्या किया जाना चाहिए। वो एक अलग विषय हैं। लेकिन इसका एक मूल कारण तो हैं पेड़ों की कटाई, पेड़ों का कम होना। मैं देख रहा हूँ, कि एक तरफ जैसे निर्ममता–पूर्वक लोग पेड़ काटते रहे हैं। उसी प्रकार से हम

देख रहे हैं कि एक समानान्तर अच्छी प्रवृत्ति पैदा हो रही है, पेड़ों को लगाने की। ये बहुत बड़ी बात है और इसमें आप सब लोगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं सबसे पहले यहाँ जो माहैल बना है। इसके लिए आपको बधाई देता हूँ और एक ही जगह से हर चीजों का अनुश्रवण हो सकेगी, उसकी चर्चा हो सकेगी। अब आम लोगो को सहूलियत होगीं पहले यत्र–तत्र बिखरे हुए थे। तो मै समझता हूँ कि आपस में चर्चा करने से इसके साथ–साथ गंगा जी की भी चिंता की है। हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षा से इस पर चिंता प्रकट की जाती है। पहले भी प्रकट की जाती रही है, लेकिन चिंता तक ही जाती थी। अब इसके आगे एक और आता है जब बड़ा जोर–शोर से बातें कही जाती है। अब हम देख रहे हैं कि इन दिनों निर्मलता पर बहुत जोड़ है। अविरलता हो गई लेकिन जबतक निमर्लता और अविरलता सत्त प्रवाह हो और निर्मल हो, दोनो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि गंगा की रक्षा की जा सकती हैं। हम लोग खुद देख देख रहे हैं अपने बचपन के दिनों से लेकर आज तक और उतने दिनो की बात तो छोड़ दिजिये। 40 वर्षों का, 45 वर्षों का गैप की बात तो छोड़ दीजिए। पिछले 8–9 वर्षों में जो कुछ भी हमलोगों ने गंगा नदी की स्थिति को देखा हैं पटना में ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। हम और एक स्थान पटना से बता सकते हैं कि गंगा नदी की क्या स्थिति होती जा रही है, सिकुडती जा रही हैं छिछली होती जा रही है। प्रवाह घटता जा रहा हैं और प्रवाह आता कितना हैं। अब जिस गंगा जल कि पवीत्रता की बात हम लोग करते थे वो गंगा नदी के जल में अपनी कुछ खासियत है। वो खासियत अब वो हैं कहाँ। जो हिमालय के गंगोत्री से निकली है और जो विभिन्न इलाको से गुजरते हुए यहाँ आती थी हिमालय पर्वत से ओर इसके अंदर इस जल के अंदर कुछ खासियत थी। वो है

कहाँ? वो गंगा जल कहाँ है, बिहार में तो एक बूंद गंगा जल का नहीं आ रहा हैं। जिस गंगा जल की महिमा की बात होती है। और बिहार में जो कुछ भी गंगा नहीं के नाम पर प्रवाहित हो रही नदी है। इसका आता कितना हैं बस 400 क्यूसेक पानी आता हैं। ये बिहार ही हैं जो गंगा नदी के प्रवाह को बढ़ाता है। जहाँ से नदी निकली है। वहाँ से लेकर बिहार के पहले तक तो गंगा नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने की कितनी योजना बनी और जो हम लोग सोचते हैं कि जल विद्युत के लिये या सिचाई के लिए हम ने टैंक बना दिया और सब रोक दिया, फिर पानी तो हम छोड़ ही देते हैं। कई तरह की बात क्यो करते हैं ? लेकिन वो जो उसकी quality थी, उन जगहों से, जहाँ से गुजरती थी गंगा नदी और उस पानी में जो कुछ अपनी गुणवत्ता थी वो अब है कहाँ ? सब समाप्त होते चली जा रही है। मै नहीं जानता संगम नदी तट तक कितना गंगा नदी का जल पहुंचता है। बनारस में कितना गंगा नदी का जल पहुंचता है। वो गंगा जल जिसकी बात करते हैं। जिसकी महिमा की चर्चा हम लोग अपने बचपन से सुनते आए बिहार में तो बिलकुल नहीं और बिहार में तो 400 क्यूसेक पानी आता है और बिहार जब छोड़ता है, गंगा नदी बिहार से बाहर जाती है तो 1600 पानी का प्रवाह है, तो बिहार के लोग जिम्मेवार नहीं है, contribute करता है। और पता नहीं कौन कौन सी योजना बनाने के बारे में विचार चल रहा है? मैने तो अभी गंगा river basine authority की फिर meeting थी, नई सरकार के बनने के बाद भी उसमें भी हिस्सा लिया और मैंने अपनी बातें रखी।